14.31½ hrs.

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 24 and 55)

Shri Parashar (Shivpuri): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961".

The motion was adopted.

Shri Parashar: I introduce the Bill.

14.32 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMEDND-MENT) BILL*

(Amendment of section 24)

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939".

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

14.32½ hrs.

ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL*

Shri A. T. Sarma (Chatrapur): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of an All India Ayurvedic Medical Council for India, maintenance of an Ayurvedic Medical Register for the whole of India and for matters connected therewith.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of an All India Ayurvedic Medical Council for India, maintenance of an Ayurvedic Medical Register for the whole of India and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

Shri A. T. Sarma: I introduce the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Next Bill, Shri Sivamurthi Swamy—not here.

Bills for consideration. Dr. Ram Manohar Lohia is not here. He has authorised Shri Ram Sewak Yadav.

14.33 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Omission of Section 109) by Dr. Ram Manohar Lohia.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898, में आगे संशोधन करने वाला विधेयक सदन के सामने पेश है इसको डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने रखना था लेकिन चूंकि वह कुछ कारणवश सदन में इस समय उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैं इस बिधयक को सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता

*Published in Gazette of India Extraordinary, PartII, section 2, dated 5-3-65.

हूं कि सदन इस पर विचार करेगा और विचार करने के बाद इसको मंजूर करेगा हालांकि मैं डाक्टर राम मनोहर लोहिया की तरह से तो इसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो धारा 109 है यह अपराध रोकने की धारा कही जाती है । आज तक इस सदन में अक्सर जो प्रीवेंटिव डिटैंशन ऐक्ट है या जो भारत रक्षा कानून है इसके तहत पकड़े गये राजनीतिक लोगों और बड़े लोगों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है लेकिन आज इस सदन में यह पहला अवसर है कि देश के लाखों गरीब लोगों को इस कानून का शिकार बनाया जाता है उसकी चर्चा आज यहां प्रथम बार होने जा रही है और मैं समझता हूं कि इस 109 धारा का जो इस्तेमाल है इसका जो उद्देश्य है, उनको जो जानते हैं इस सदन के माननीय सदस्य और जो बाहर इसकी प्रतिक्रिया है हिन्दुस्तान में जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया है उसके विपरीत है और मैं उनको इस सदन के सामने और मंत्री महोदय के सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी बात और तर्क इस आशा के साथ पेश करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

इस धारा 109 का मतलब है कि अपराध न हों इसलिये इस के अन्दर जो पकड़े जाते हैं उस में तीन उद्देश्य बतलाये गये हैं । तीन बातें कही गई हैं। अगर कोई आदमी अपने को कहीं छिपाये, दूसरा उस का जरिया माश न हो, कोई रोटी-रोजी का जरिया न हो और उस से जब पूछताछ की जाय तो वह कोई संतोषजनक उत्तर न दे वहां पर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो खट्ट से उसको 109 के अन्तर्गत चालान कर के जेल भेज देते हैं । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के सामने अनुरोध करूंगा कि छिपाना कोई किस जगह पर है जिस कारण से है, इस को कौन तय करेगा ? दूसरे जरिया माश....

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): May I interrupt the hon. Member for a minute? While the hon. Member is quoting a section of the law I would request him either to read the actual section or use the words which are used in the law itself. He just now said *"chalan karke jail me bejdenge"*. I do not know whether section 109 of the Criminal Procedure Code gives power to the magistrate to do that.

श्री रामसेवक यादव : मैं जानता हूं। मैं उस के बारे में भी कह दूं कि अगर वह जमानत नहीं देता तो जेल में उसे रखना पड़ेगा । यह है उस का उद्देश्य । अगर इतनी बारीकी मंत्री महोदय निकालते हैं तो मैं समझता हूं कि इस तर्क का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है । अगर वह जमानत नहीं देता, कोई गरीब आदमी उस को जमानत नहीं मिलती है तो उस को जेल में ही रहना पड़ेगा और जेल में रहते हैं लाखों आदमी। अगर मंत्री महोदय जानते होते तो शायद ऐसी बात नहीं कहते । छिपाना, जरिया माश का न होना, अगर उस जरिया माश के अभाव को देखा जाय तो हिन्दुस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कि पास कोई जरिया माश नहीं है। उन के पास खेती नहीं है। श्रीमन्, उन के पास नौकरी नहीं है, उन के पास रोजगार नहीं है, कौन उन को खेती, रोजगार दे ? क्यों उन के पास खेती नहीं है ? उन का गरीब होना ही एक अपने में अपराध है । उस अपराध के मातहत अगर इस दफ़ा की इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाय तो उन को जेल में जाना पड़ता है ।

इसी तरीक़े से अगर संतोषजनक जवाब न देंगे, अगर यह तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो उस का चालान होता है और आये दिन हजारों लाखों लोग जेलों में

[श्री रामसेवक यादव]

रहते हैं और हिन्दुस्तान-भर की अगर तालिका एकत्रित की जाये, आंकड़े इकट्ठे किये जायें तो श्रीमन्, लाखों लोग हिन्दुस्तान में 109 धारा के अन्दर जिनका कि केवल यह पाप माना जाता है कि उन के पास कोई जरिया माश नहीं है, ग़रीब लोग हैं, इसलिये उन को जेल में जाना पड़ता है और अगर पता लगाया जाये तो 30, 40, 50 हजार व्यक्ति हर वक्त इस धारा 109 के अन्तर्गत जेल में रहते हैं, हमेशा रहते हैं और आने जाने वालों की संख्या अगर पता लगाई जाये तो वह तो फिर लाखों में पहुंच जाती है । अब इस धारा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ? इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है बदले के लिए । कोई गरीब होता है उस पर जरूरत के लिए और पुलिस की चौकसी दिखाने के लिए होता है । बदला किस तरह से ? अगर कहीं पर कोई पुलिस का आदमी अन्याय करे या कहीं जमींदार या वहां का जागीरदार या कोई धनपति व्यक्ति किसी गरीब के प्रति अन्याय करे और कोई आदमी उस के खिलाफ़ आवाज़ उठाए और अन्याय करने से टोक दे तो फिर पुलिस से मिल कर उस व्यक्ति को 109 में चालान करके जेल भेज दिया जाता है । इसके साथ ही साथ 109 में श्रीमन्, यह भी होता है कि गांव में अगर कोई गरीब आदमी किसी बड़े जमींदार जो पुराना है और आज भी वे लोग किसी-न-किसी शक्ल में एक हैसियत वाले लोग हैं, उनके यहां बेगार करने नहीं जाता, कम तनख्वाह पर काम करना पसन्द नहीं करता है तो चूंकि पुलिस की और उसकी दोस्ती होती है उसका धारा 109 में चालान करा दिया जाता है और बाद में वही जागीरदार या जमींदार जमानत करता है और वह बेचारा आदमी उसके वहां हल की मूंठ पकड़ कर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बय कर देता है । हमेशा के लिए उस की किस्मत बंध जाया करती है । यह है धारा 109 । ऐसे आदमियों की है यह धारा 1091 में पंजाब का एक मामला बतलाऊं जो कि सन् 1951 का है । वहां जब पुलिस वाले एक व्यक्ति तेजा सिंह को पीट रहे थे तो एक कर्तार कौर नामक स्त्री ने उन्हें मनाह किया तो पुलिस वालों ने बदले की भावना से प्रेरित हो कर उस महिला का 109 में चालान कर दिया । 1951 में पंजाब के हाई कोर्ट का फैसला है और उस में वह जाकर छूट पायी । इस तरीके से यह सारी चीजें चलती हैं ।

अगर कोई आदमी गरीब है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उसको जेल भेजने के लिए वह काफ़ी है, क्योंकि इस धारा के इन्ग्रेडियन्स में यह भी शामिल है कि अगर किसी के पास जरिया-मुआश नहीं है, रोजी-रोटी का साधन नहीं है, तो उसके विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।

इस धारा का इस्तेमाल जरूरत के लिये भी किया जाता है । क्या जरूरत ? जेलों में कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन को कैदियों के जरिये ही कराया जाता है, जैसे भंगी का काम—पाखाना उठाना, धोबी का काम—कपड़े धोना, मोची का काम—जूतों की मरम्मत करना और उन को तैयार करना, नाई का काम—बाल बनाना, आदि । यह न समझा जाये—माननीय सदस्य, श्री शर्मा, यह न समझें—कि यह धारा छोटी जातियों और ग़रीबों के विरुद्ध ही इस्तेमाल होती है । यह बड़ी जातियों के ग़रीबों के लिए भी इस्तेमाल होती है । जेल में रोटी बनाने के लिए ग़रीब ब्राह्मण का चालान भी धारा 109 में किया जाता है । जेल और पुलिस के अधिकारियों में हमेशा बात-चीत चलती रहती है कि इस समय हमारे यहां भंगी का काम है, जिस व्यक्ति को धारा 109

के अधीन भेजा गया था, वह अब जाने वाला है, किसी और को भेज दो । धारा 109 का इस्तेमाल इस बात को दृष्टि में रख कर किया जाता है कि किन-किन लोगों की जेल में जरूरत है और किन लोगों का चालान कर के भेजना है ।

इसके अतिरिक्त इस धारा का इस्तेमाल पुलिस चौकसी ज़ाहिर करने के लिए भी किया जाता है । हमारे मंत्री जी भले आदमी हैं, लेकिन हम को केवल भल-मनसाहत और मीठी बात से ही नतीजे नहीं निकालने चाहियें, जैसा कि इस सदन का और देश का दस्तूर बन गया है । भल-मनसहत की जांच होनी चाहिये उस के परिणामों और फलों को देख कर । अगर गृह मंत्री महोदय भले आदमी हैं तो उस का एक नतीजा यह निकलना चाहिये कि देश में जरायम घटें, मुजरिम लोगों को सज़ा मिले, ग़रीबों का शासन में विश्वास जमे और आतताइयों में शासन का भय पैदा हो । अगर मंत्री महोदय और मंत्रालय यह नहीं कर पाते, तो चाहे वह संतरे या अंगूर जैसे मीठे हों, उस का कुछ मतलब नहीं है, उस से कड़ुवाहट ही पैदा होगी, अन्ततोगत्वा उस का कई नतीजा नहीं निकलने वाला है ।

कैरों हत्या-कांड के लिए कोई नहीं पकड़ा जायगा । अगर स्त्रियों का अप-हरण हो, तो कोई नहीं पकड़ा जायेगा । सन्याल हत्या-कांड के लिए कोई नहीं पकड़ा जायेगा । लेकिन पुलिस अपनी कारगुज़ारी और चौकसी दिखाने के लिए और मजिस्ट्रेट यह दिखाने के लिए कि हम हर महीने कितने मुकदमों का फ़ैसला करते हैं, धारा 109 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़े जाते हैं वे कुबूल कर लेते हैं और उन को साल भर के लिए जेल में या किसी ज़मींदार की बेगार में रहना पड़ता है । इस प्रकार अपनी कारगुज़ारी को दिखाने के लिए धारा 109 का प्रयोग किया जाता है कि पुलिस ने इतने चालान किये और मैजिस्ट्रेट ने इतने मुकदमों का फैसला किया और यह तादाद बराबर बढ़ाई जाती है ।

इस देश के हरिजन, पिछड़ी जातियों के--और ऊंची जातियों के भी—गरीब लोग आये दिन इस धारा का शिकार होते हैं । मैं नहीं समझ पाता कि हमारे संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों और जनतंत्र के रहते हुए आज धारा 109 कहां तक उपयुक्त है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सभी और समय मिलना चाहिये । इस बिल में माननीय सदस्यों को दिलचस्पी है, इस लिये इस का टाइम बढ़ा दिया जाना चाहिये ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, इसलिये इस का समय बढ़ाना चाहिये ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : लोगों को पकड़ कर कांजी हाउस में डाल दिया जाता है । इस बिल का समय बढ़ाया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पंद्रह मिनट ले लिये हैं । अजब वह तीन चार मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री रामसेवक यादव : मैं तीन चार मिनट में खत्म नहीं कर पाऊंगा । अगर मैं अपने पूरे तर्क रख पाऊंगा, तभी कुछ मतलब निकलेगा । यह कोई दल-विशेष का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्यों की मर्ज़ी है कि इस बिल पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये ।

धारा 109 के अधीन पकड़ने के लिये मोमबत्ती, दियासलाई, लाठी और सावर, यही आधार हैं । अगर माननीय

[श्री रामसेवक यादव]

मंत्री आई० सी० एस० अफसरों और अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये नोट्स और रिपोर्ट्स को छोड़ दें और अपनी याददाश्त को ताज़ा करें, तो वह यही देखेंगे कि वही मोमबत्ती, दियासलाई , लाठी और सावर निकला और किसी को साल भर के लिए जेल भेजने का मसाला मिल गया ।

श्री बी० चं० शर्मा : (गुरदास पुर) क्या माननीय सदस्य भी कभी पकड़े गए हैं ?

श्री रामसेवक यादव : माननीय सदस्य खुशामद करते रहें, उन का नम्बर भी आ जायेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वही मोमबत्ती, दियासलाई, लाठी और सावर हर मुकदमे में बार-बार पेश होते हैं । मैं समझता हूं कि उन को जला देना चाहिये या समुद्र या नदी में फेंक देना चाहिये । जहां ये चीजें पेश की गई, वहां मेजिस्ट्रेट महोदय ने साल भर के लिए जेल भेज दिया ।

जहां तक झूठी गवाहियां देने का सम्बन्ध है, अगर मैं "जर्नल आफ दि इंडियन ला इंस्टीट्यूट" में से कोट करूं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह दिल्ली में, जहां जनतंत्र का केन्द्र है, जहां मंत्री आदि सब लोग रहते हैं और जो केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र है, धारा 109 के अन्तर्गत 1385 गिरफ़तारियां हुई और किस तरह से मुकदमे चले । इस में यह भी बताया गया है कि 19 मुकदमों में एक गवाह, 17 मुकदमों में दो गवाह और 14 मुकदमों में एक गवाह—वही गवाह पेश किये गये और उन के साथ वही मोमबत्ती, वही लाठी, वही सवार और वही दियासलाई भी पेश किये गये । और शिकार होते हैं ग़रीब आदमी ।

यह धारा कितनी अन्यायपूर्ण है, इसका अन्दाज़ा आप इस से लगा सकते हैं कि मानवाधिकारों के बारे में यूनेस्को की जो अठारहवीं रिपोर्ट आई है, उस में दिया हुआ है कि कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां जमानत की भी व्यवस्था नहीं है, जहां किसी को जेल में रखना पसन्द नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच में भेदभाव है । इस के अतिरिक्त ऐसे भी देश हैं, जहां फांसी का जुर्म साबित होने पर भी, फांसी की सज़ा होने पर भी, वह सज़ा खत्म करके अभियुक्त को केवल जेल में रखा जाता है ।

उन देशों को देखिये और उस देश को देखिये, जो गांधी और जनतंत्र का देश है, जहां रात-दिन गांधी और जनतंत्र का नाम लिया जाता है । यहां पर बेरोज़गार होना और किसी जाति-विशेष का होना एक अभिशाप है, क्योंकि भंगी ज़रूर जेल जायेगा पाखाना साफ़ करने के लिए और ब्राह्मण को खाना पकाने के लिए जाना पड़ेगा ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : भंगियों की जगह सांसी ज्यादा लिये जाते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : क्या जनतंत्र में ग़रीब होना या किसी जाति-विशेष का होना जुर्म है कि व जेल में भेज दिये जाते हैं ? 1956 में हिमाचल प्रदेश में जस्टिस रामभद्र ने एक फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई कभी पहले सज़ा काट चुका हो, तो भी यह ज़रूरी नहीं है कि उस को सज़ा दे दी जाये । लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर किसी को पहले सज़ा हुई हो और धारा 109 में उस का चालान हो गया, तो फिर किस सबूत, बहस-मुबाहसे, जिरह और गवाह की ज़रूरत है । उस को जेल भेज दिया जाता है। आज यह इस धारा की स्थिति है । इसको रखने से अपराध घटेंगे नहीं, बल्कि बढ़ेंगे ही ।

आप यह भी देखें कि इसकी पकड़ में ज्यादातर कौन लोग आते हैं ? ऐसे लोगों को इस धारा के अन्तर्गत पकड़ा जाता है जिनका न कोई जुर्म होता है और न ही जुर्म करने की उनमें कोई आदत होती है, जो न अपराधी

होते हैं और न ही अपराध करने की प्रवृत्ति उनमें विद्यमान होती है । जब एक आदमी को बिना अपराध के जल में भेज दिया जाता है और एक साल तक वह जेल काट लेता है कैदियों के बीच रह जाता है तो दूसरे कैदियों की आदतें वह सीख कर बाहर आता है बुराई ले कर ही बाहर आता है । ऐसा अन्याय ऐसा कुशासन ऐसी सरकारी मशीनरी है कि भूखे रहने के लिए गरीबी के कारण किसी जाति विशेष से सम्बंधित होने के कारण आदमी को जेल भेज दिया जाता है और जिस को जेल भेज दिया जाता है वह अन्ततोगत्वा अपराधी ही बन जाता है । इसलिए मैं कहता हूं कि धारा 109 अपराधों को घटाने में सहायक नहीं होती है बल्कि अपराधों को बढ़ाने में ही मदद देती है ।

विदेशों की बात भी मैं कहना चाहता हूं । कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह की धारा हो । अमरीका को भी आप देखें । नीगरो और हब्शी लोगों को छोड़कर जो गोरे लोग वहां हैं उनको भी धारा 109 की तरह की किसी धारा में पकड़ने की कोई गुंजाइश वहां नहीं है ।

मैं अनुरोध करता हूं कि यह जो सस्ता नुस्खा है कि किसी को भी धारा 109 में गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके तहत पुलिस और मेजिस्ट्रेट जो कारगुजारी दिखाते हैं उसके परिणामों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि बजाय अपराध घटने के बढ़ रहे हैं । इसका एक और भी दुष्परिणाम हो रहा है । इससे शासन में ढीलापन आता है, आलस्य आता है । इस तरह जो शार्टकट ढूंढे जाते हैं पगडंडियों की तलाश की जाती है इससे शासन की निपुणता और कुशलता नहीं बढ़ती है । अगर यह धारा बनी रहेगी तो राधा और कृष्ण प्रेमी और प्रेमिकायें अगर कहीं किसी जगह पर आस लगाये बैठे होंगे तो उनको भी पकड़ कर अन्दर बन्द किया जा सकता है । इतने साल हमें आजाद हुए हो गए हैं लेकिन इस धारा को आज तक नहीं हटाया गया है । अब तो आप इसको समाप्त करें और संविधान में मनुष्य के अधिकारों की जो बात आपने रखी है, बिना इस धारा को समाप्त किये उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है । अगर जाति अथवा गरीबी ही अपराध का कारण न हो तो इसे आप समाप्त करें यही मेरा निवेदन है ।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898, be taken into consideration."

Shri Onkar Lal Berwa: I beg to move:

> "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by the 1st August, 1965".

Mr. Deputy-Speaker: What about the other amendment for referring the Bill to a Select Committee? Nobody is moving it. This motion and the amendment are before the House. May I have an idea as to how many Members want to participate? I find a number of hon. Members want to participate. We will extend the time by half an hour.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): Sir, it would have been better had this amendment been for the whole of the provisions from sections 107 to 115, instead of merely section 109. Unfortunately this section alone has been picked out of the whole. It is true and I do support my hon. friend, Shri Yadav, when he said that this section is misused more and more these days. In the 1952 elections, when Mr. Rikhab Das fought Mr. Ridhichand Paliwal who was a Minister and who is now a Member of Parliament, he was a candidate for the Hindaun constituency in the 1952 elections. But during the election, for 20 days, ten times 15 Jan Sangh workers were arrested and were not released till the day when the election started. This fact was brought to the notice of the tribunal. I request the Minister to look into that case. It is re-

[Shri U. M. Trivedi]

ported in Vol. IX ELR page 115.

Two of the judges of the tribunal remarked that the Sub-Divisional Magistrate acted arbitrarily, with a guilty knowledge, helped the Congress Party and deliberately arrested all the Jan Sangh workers under section 109. They were released on the following day after the security was furnished. So, the poor candidate remained in the lock-up throughout the night and till 2 o'clock on the day of election. He was not allowed to do propaganda on the previous day and also on that day. This is the strongest case which suggests that this section 109 must be amended. I do not say it should be dropped. It might be a useful provision, but it should be suitably amended. For that, this Bill must be circulated for eliciting public opinion.

I will draw the attention of the Minister to this judgment in the case I have quoted. Unfortunately, the application did not succeed because the mischief was done by the Government officer and it could not be proved that it was done with the connivance of the candidate concerned. But a tremendous amount of mischief could be done. The judgment says:

> "Whatever the merits of the proceedings under section 107 of the Criminal Procedure Code with which the tribunal is not directly concerned, it was hardly desirable to have kept these persons throughout the night in the lock-up or even to have arrested them on the eve of the polling day and quite unnecessarily to create an impression that the chances of the petitioner were being prejudiced."

So, my contention is that it is high time that this whole measure is circulated and if possible the whole of these sections should be amended. In Bijolia, under sections 107 and 109, 84 Jan Sangh workers—not one or two but 84 Jan Sangh workers—have been arrested and put behind the bars because the panchayat elections have come. I have yet to find the day when I will be able to get them of. Therefore, it is high time that Government should open its eyes to these sections an dsuitably amend them.

श्री सरजू पाण्डेय : सबसे पहले तो मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं और साथ ही मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं दण्ड शास्त्रियों का यह मत है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सजायें देने से वे रुकते नहीं हैं बल्कि उसके कारण बढ़ते हैं । इसलिए अपराधों के कारणों को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिये । पिछले जमाने में अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का नियम था और छोटे मोटे अपराधों के कारण लोगों के हाथ काट दिये जाते थे लेकिन अपराधों में इससे कमी नहीं हुई बल्कि वे बढ़ते ही गए ।

18 साल हमें आजाद हुए हो गए हैं लेकिन आज भी इस धारा को हमने बनाये रखा है । दुनिया के किसी भी स्वतंत्र देश के लिए इस तरह की धारा को बनाये रखना शर्मनाक बात है । इस तरह से किसी आदमी को जेल में बन्द करना जिसका कोई अपराध साबित न हो कहां तक न्यायोचित है ? हमारे भाई राम सेवक यादव जी ने मिसालें दी हैं । गरीब लोगों की जिंदगियां पुलिस के हाथों में दे देना, पुलिस के सुपुर्द कर देना, मैं समझता हूं कतई ठीक नहीं है और पुलिस भी वह जिसके बारे में इलाहाबाद के एक हाई कोर्ट जज ने कहा था कि हिन्दुस्तान की पुलिस नंगों की फौज है इस में किस किस को कपड़ा पहनाया जाए, समझ में नहीं आता है । उसके सुपुर्द लोगों के जीवन को कर देना कतई तौर पर अन्यायपूर्ण है ।

अगर आप धारा 109 को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस में कोई जरूरत नहीं है

सफाई की कोई जरूरत नहीं है सबूत की या गवाह की । हमारे भाई ने ठीक कहा है कि जेल को भंगी की जरूरत हुई तो पुलिस वालों ने भंगी को पकड़ा और जेल भेज दिया, रोटी वाले की जरूरत है तो गरीब ब्राह्मण को पकड़ कर जेल भेज दिया जाता है, धोबी की जरूरत होती है तो उसको पकड़ कर भेज दिया जाता है । जितना दुरुपयोग इस ताकत का हो सकता है किया जा रहा है ।

जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब कितने ही कांग्रेसियों को भी 109 के अन्तर्गत पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया था । बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं तक को पकड़ कर बन्द कर दिया जाता था । मुझे यहां तक याद है कि स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के सम्बंध में कहा जाता है कि उनको भी पुलिस ने पकड़ कर 109 में बन्द किया था ।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि हिन्दुस्तान में अपराधों को बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की है । पुलिस मंत्री जो यहां बैठे हैं । अगर वह अपने ये कपड़े उतार कर किसी थाने में चले जाएं और थानेदार को मालूम न हो कि यह मंत्री हैं, तो हो सकता है कि वह उनको उठा कर बन्द कर दे । ऐसी पुलिस के हाथ में आप इतना अधिकार इस धारा द्वारा दे रहे हैं, यह कतई तौर पर गलत है ।

15 hrs.

मुझे मालूम है कि किस तरह से गरीब लोग इस धारा के कारण तंग किए जाते हैं । बहुत से न्यायालय इस धारा के विरुद्ध अपनी राय दे चुके हैं । लेकिन सरकार इसको बनाए हुए है गरीब लोगों को पकड़ कर बन्द करने के लिए । आज इस देश में बोलने की आजादी केवल इस सदन में ही है और सदन से भी वह खत्म होती जा रही है । बाहर तो कोई स्वतंत्रता है ही नहीं । अगर कोई जरा बात करे तो उसको पकड़ कर दफा 109, 110 या 379 में बन्द कर दिया जाता है । न जाने कितनी इस प्रकार की दफाएं बना रखी हैं । पुलिस के आगे कोई सबूत या शहादत नहीं चलती । कुछ आवारा लोगों को सड़क पर से पकड़ कर उनका बयान करा दिया जाता है और उसके आधार पर लोगों को बन्द कर दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि इस धारा को हटा दिया जाए, लेकिन अगर इसको रखा ही जाता है, तो इसमें कुछ ऐसा सुधार कर दिया जाए कि इसके द्वारा गरीब लोगों को न सताया जा सके । जो गरीब लोग धनी लोगों की बेगार नहीं करते उनको वे लोग अपने जान पहचान के पुलिस वालों से कह कर दफा 109 या 110 में पकड़वा देते हैं और उनका चालान करवा देते हैं । मुझे यह सब चीज अच्छी तरह मालूम है क्योंकि मैं लगभग नौ साल जेलखाने में रह चुका हूं । आज जो सन 1946 के बाद कांग्रेसी दिखायी देते हैं, जो आजादी का एक बड़ा ढोंग रचते हैं, उनसे हम कम जेल नहीं रहे हैं । हमने देखा है कि वही लोग इस धारा में जेल भेजे जाते हैं जिनके पास अपने बचाव के लिए पैसा नहीं है । ऐसे गरीब आदमी भेजे जाते हैं जो वकील नहीं कर सकते, जिनको न शहादत मिल सकती है और न जो अपनी सफाई दे सकते हैं । जिस मुल्क में न्याय इतना मंहगा हो उस मुल्क में इस तरह की धारा होना बड़ा अन्यायपूर्ण है । इसलिए मैं पुलिस मंत्री से कहूंगा कि इस पर संजीदगी से विचार करें । यह पूरे देश का सवाल है और मैं समझता हूं कि किसी भी आजाद प्रजातांत्रिक देश में इस तरह की धारा कानून में नहीं है । मेरा अनुरोध है कि इसको वापस लिया जाए, पर अगर इसको रखना ही है तो इस तरह इसमें सुधार कर दिया जाए कि गरीबों के प्रति इस धारा का इस्तेमाल न हो सके । ऐसा होगा तभी जा कर सही मानों में जनता में प्रजातंत्र के प्रति विश्वास पैदा हो सकेगा ।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : यह जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है, मैं

[श्री पाराशर]

इसका विरोध करता हूं । मालम होता है कि प्रस्तावक महोदय ने इस धारा को ठीक से पढ़ा नहीं है, नहीं तो वह इसको निकालने का अनुरोध न करते । अगर वह इसको गौर से पढ़ लेते तो इस बिल को पेश न करते इसमें क्लाज ए में लिखा है :

"such person is taking such precautions with a view to committing any offence,".

अगर कोई जुर्म करने की नीयत से अपने आप को छिपा रहा है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए । लेकिन अगर इसको निकाल दिया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि कोई जुर्म करने की दृष्टि से अपने को मजे में छिपा सकेगा । अगर हमारे समाज वादी भाई या श्री रामसेवक यादव यह चाहें तब तो इसको निकाल दिया जाए । पर मैं समझता हूं कि वह ऐसा नहीं चाहते । अगर वह इस धारा को समझ लेते तो ऐसा बिल न पेश करते ।

दूसरे इसमें लिखा है :

"or who cannot give a satisfactory account of himself."

जो अपने बारे में ठीक से न बता सके कि वह कौन है और कहां से आया है आदि, उसको पकड़ना ही चाहिए । अगर यादव जी इस को समझ लेते तो वह यह बिल न लाते । इसमें धारा का दोष नहीं है दोष है उनकी अक्ल का । इस सिलसिले में मुझे एक बात याद आती है । एक विद्वान ने अपने लड़के को एक ज्योतिषी के पास ज्योतिष सीखने के लिए भेजा । जब वह पढ़ कर आया तो उसने परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा कि बताओ कि मेरे हाथ में क्या है । लड़के ने कहा कि आपके हाथ में एक गोल चीज है, उसमें छेद है और वह सफेद है । पिता ने समझा कि लड़का तो पढ़ा तो ठीक है । फिर उससे पूछा कि वह चीज क्या है तो लड़के ने कहा कि वह चक्की का पाट है । इस पर पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने समझ लिया कि पढ़ाने वाले का कसूर नहीं था, कसूर लड़के की अक्ल का था । पिता के हाथ में मोती था, जो कि सफेद भी था, गोल भी था और उसमें छेद भी था । तो विद्या तो ठीक थी लेकिन यह लड़के की बुद्धि की कमी के कारण था कि उसने कहा कि आपके हाथ में चक्की का पाट है ।

यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इसको पढ़ लेते तो इस बिल को न लाते । जो आदमी जुर्म करने की गरज से छिप रहा है या जो अपने बारे में ठीक नहीं बता सकता, उसको पकड़ा जाना चाहिए ताकि वह जुर्म न कर सके । अगर इस धारा को निकाल दिया जाएगा तो इसका बुरा परिणाम होगा ।

श्री रामसेवक यादव : शायद आप नई वकालत करना चाहते हैं इसलिए ऐसी दलीलें दे रहे हैं ।

श्री पाराशर : आप सुनिए । आप कह चुके, अब आपको सुनना है ।

अब आगे इसमें लिखा है :

"ostensible means of subsistence".

अगर उन्होंने इन तीन शब्दों को "आस्टेंसिविल मीन्स आफ सवसिसटेंस" पढ़ लिया होता तो शायद उनको इस पर ऐतराज न होता । आस्टिंसिविल कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शी को, मीन्स कहते हैं साधनों को । सवसिसटेंस का जो उन्होंने अर्थ किया है "भरण पोषण या जरिया माश" वह सही नहीं है । उसका अर्थ है जीवन रक्षा । हर आदमी किसी न किसी तरह अपनी जीवन रक्षा करता है । अगर वह खुद नहीं कमाता तो उसका लड़का उसको खिलाता है या वह मांग कर खाता है । लेकिन अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है और जो मजे में खाता पीता है और हट्टा-

कट्टा है यह देखने की बात है कि वह कोई जुर्म तो नहीं करता । इसलिए इसका रहना जरूरी है ।

इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इसको वापस ले लिया जाएगा ।

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): Sir, I am definitely of the opinion that this section is an anachronism and it should be radically recast. We thought that in view of the definite provisions that were made in the Constitution and the Fundamental Rights guaranteed, especially under article 21 of the Constitution, sections like this section would be struck down as illegal. Unfortunately, you remember, in the leading case of Shri A. K. Gopalan, the Supreme Court took, with great respect, a very narrow and rigid view. You know that I had the privilege to deliver a lecture on constitutional law in the city of Bangalore. Shri Setalvad, the former Attorney-General of India strongly commented on that judgment and pointed out that that is not the proper view which inspired the Constitution-makers. Unfortunately, that view is still there, otherwise this section which imposes a fetter on the citizen's liberty would have been struck down as un-constitutional.

Sir, I am not one of those who want to repeal all laws which may fetter the hands of the guardians of law and order. Especially after the horrible murder of the former Solicitor-General, Shri Sanyal, and the tragic assassination of Shri Pratap Singh Kairon on the outskirts of the Union Territory of Delhi, I would not like to weaken the police force in any manner. But I am definitely of the view that this section has been abused, as hon. Members have already pointed out. You know, in Bengal this section has been abused and has been utilised against freedom fighters. In those great days of the struggle for emancipation the executive had resorted to this section for the purpose of putting behind prison bars young men who had committed no crime or were going to commit no crime. As you know, Sir, the language of the section is such that it is very elastic and some High Court judges have commented very strongly on it. The language is " . . . within such limits a person who has no ostensible means of subsistence . . . ". A young man who has not got any employment but who is the son of a very respectable person is arrested and kept in jail. Many a time the judges have commented that it should not have been done. Very few people go to the High Court or the highest court to vindicate their rights. In these days of high prices and spiralling of prices of foodstuffs anybody can come within the scope of this section because it is very loosely worded. Clause (b) should go, though clause (a) may be all right. A Full Bench of the Nagpur High Court has deprecated the arrest of people who have been very well known, who have known places of accommodation, under this section.

We are now citizens of a sovereign democratic republic. We have pledged to establish the rule of law. This is not is keeping with the fundamental concept of rule of law and so it should be altered.

I would, therefore, ask the hon. Minister to consider whether he should accept the suggestion of referring it either to a Select Committee or to the public for opinion, gather responsible opinion, find out the difficulties they will have to face if this section is altered and then present before us a suitable amendment. That should be done to make it more consonant with the democratic rights and with the fundamental freedom which we have guaranteed to ourselves.

Shri Siddiah (Chamarajanagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this section was incorporated in the Code of Criminal Procedure in the year 1898. That means that nearly 67 years have

[Shri Siddiah]

passed. Perhaps there was some reason for the incorporation of this section at that time. Now things have changed very much, and we are working under a democratic constitution.

If you look at clause (b), it says "a person who has no ostensible means of subsistence". So, any person who happens to be poor and who is unemployed can be proceeded against under this section very easily. As hon. Members have already pointed out, this section has been misused on very many occasions and many people, specially poor people, who could not prove they have got ostensible means of subsistence, who could not give a satisfactory account of themselves, have been proceeded against and they have been put behind the bars. It is true that they can be released if they can prove to the satisfaction of the authorities that they are not so, or execute a bond. But in many cases it often happens that they are not able to get even sureties. As lawyers know, when the police have no other reason to apprehend a person, they naturally resort to this section 109. Rich people who want to proceed against poor people influence the police officers and see that the police take action under this section. So, I am of the opinion that clause (b) of this section should be deleted.

So far as clause (a) is concerned, I am not in favour of deleting it completely. It may be recast in a proper way. That clause in its present form is not in keeping with the fundamental rights guaranteed by the Constitution.

As suggested by other hon. Members, I also recommend that this Bill may be referred to a Select Committee or it may be sent for eliciting public opinion after which Government should take necessary action. In any case, that section should not remain in the statute book in its present form.

श्री ओंकार लाल बेरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। उधर से अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि श्री रामसेवक यादव ने इस धारा को अच्छी तरह से नहीं समझा है और उनका यह विचार ठीक नहीं है कि इसका ग़लत प्रयोग किया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वह अपना परिचय न बतायें और मेरे साथ कोटा कांस्टीट्युएन्सी में चले जायें, या मुझे छोड़ कर चले जायें, तो अगर मैं उनको धारा 109 के अन्दर दो दिन के लिए बन्द न करवा दूं, तो उनकी तबियत में जो आए करें। बाद में वह चाहे वकील और गवाह आदि कर लें और तार से परिचयपत्र मंगा ले, लेकिन उनको मालूम हो जायेगा कि इस धारा का किस तरह से दुरुपयोग होता है।

हमारे देश में अस्सी लाख आदमी ऐसे हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं और 285 लाख ऐसे हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है,, जिनमें से 120 लाख ऐसे आदमी हैं, जो अन्धे, लंगड़े और कोढ़ी आदि हैं। एम्पलायमेंट एक्सचेंज के आंकड़े अलग हैं। अगर कोटा, राजस्थान से कोई आदमी यहां 26 जनवरी या 15 अगस्त का समारोह देखने आए, तो उस को दो दिन तो यहां रहना ही पड़ता है। अगर वह सोयेगा, तो कहां सोयेगा? वह फुटपाथ पर ही सोयेगा। पुलिस वाला उस को डंडा लगायेगा, उस को खड़ा कर देगा और उससे परिचयपत्र मांगेगा। वह आदमी कहेगा कि मैं कोटा का हूं। फिर उसको गवाह लाने के लिए कहा जायेगा। आप ही सोचिए कि जब वह कोटा का रहने वाला है, तो वह दिल्ली में गवाह कहां से लायेगा। मैंने खुद दिल्ली में दो-तीन ऐसे आदमियों को छुड़वाया है, जो कि 26 जनवरी का फंक्शन देखने के लिए यहां आए थे।

आज जो स्पेयर मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका साधन यही होता है। उन को कहा जाता है कि सौ, दो सौ केसिज रोज लाओ, जिससे अपनी हांडी गर्म रहे। रास्ता चलते लोगों की टिकट कलेक्टर की तरह से एन्क्वायरी

की जाती है । अगर किसी के पास पैसे हैं, तो उससे पांच दस रुपये ले लिये, नहीं तो उसको पन्द्रह दिन के बाद छोड़ देते हैं ।

चुनाव के दिनों में इस धारा का ज्यादा उपयोग किया जाता है । ग्राम पंचायतों के चुनावों में कई लोगों को धारा 109, 107 और 370 में पकड़ लिया गया । इस धारा को विरोधी लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है । ग्राम पंचायतों के चुनावों में विरोधी सरपंचों को धर लिया गया ।

इसी तरह ग़रीब लोगों के लिए इस धारा का इस्तेमाल ज्यादा होता है । मैं समझता हूं कि आज तक एक भी इनकम टैक्स देने वाले आफ़िसर को धारा 109 में बन्द नहीं किया होगा, चाहे वह इतना बड़ा डाकू हो कि एम० पीज० के बंगलों के सामने से कार लेकर चला जाये, जो कि धारा 109 से भी ज्यादा ख़तरनाक़ है। पिछले दिनों कई जीपें और फ़ियट कारें चोरी हो गईं । कुछ दिन पहले एक मिनिस्टर का लड़का कोई कार ले जाने के बारे में पकड़ा गया था, लेकिन उस को छोड़ दिया गया । ऐसे लोगों को धारा 109 में नहीं पकड़ा जाता है, ग़रीबों को पकड़ा जाता है, जिनके पास कोई साधन नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र ने धारा 109 को समाप्त करने के लिए जो बिल सदन के सामने रखा है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं । इस काले कानून को इस देश की ग़रीब जनता पर लगाना बहुत बड़ा पाप है और बड़े दुख की बात है । अगर इस को नहीं हटाया गया, तो पुलिस वालों की गोटी इसी तरह लाल होती जायेगी और स्पेयर मजिस्ट्रेट हमेशा नाइलोन और टेरिलीन के कोट पहनते रहेंगे ।

श्री बाल्मीकी : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं अपने 32 साल के अनुभव की बिना पर कहता हूं कि इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है, इसका दुरुपयोग होता है । जहां तक न्यायालय का या मैजिस्ट्रेट का सम्बन्ध है, मैं बहुत से केस जानता हूं कि बिना विचार किये, बिना सोचे समझे, आंखें मींच कर सजा दी जाती है गवाह तक का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

आज हमारा देश मानव अधिकारों के लिए इस देश में और संसार में लड़ रहा है । जो संविधान हमने लागू किया है और अपने देश को पूर्ण रूपेण लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र घोषित किया है, उसके बाद भी मानव अधिकारों पर इस प्रकार से कुठाराघात किया जाए इस धारा को रख कर, तो यह दुख की ही बात है । इस प्रकार की और भी धारायें हैं और उन धाराओं में से यह भी एक धारा है । मैं कहूंगा कि 107, 108, 109 और 110 इन चारों धाराओं का ही दुरुपयोग होता है और इन पर फिर से विचार किया जाना चाहिये । इनका दुरुपयोग गरीब और मामूली आदमियों के खिलाफ किया जाता है । आप किसी भी दृष्टि से देखें, आप पायेंगे कि इस देश में गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है । इंसाफ महंगा है । जब मैं मिडल में पढ़ता था तो मुझे याद है कि मेरे दिमाग पर इस बात का प्रभाव पड़ा था कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है । उस वक्त मैंने एक दोहा लिखा था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं :

सच्ची न्यायालय गया, उलटा देखा न्याय ।
जज देता निज हाथ से, सिंह हाथ में गाय ।।

गरीबों को अदालतों में यह महंगा न्याय, यह वकीली न्याय, यह मैजिस्ट्रेटी न्याय नहीं प्राप्त होता है । जहां तक इस धारा के दुरुपयोग का सम्बन्ध है मुझे बहुत से केस मालूम हैं और कुछ में मुझे दखल भी देना पड़ा है और तब जाकर कहीं मामला ठीक हुआ है ।

[श्री बाल्मीकी]

जहां तक रोज़ी-रोजगार के साधनों का सम्बन्ध है यह ठीक है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम गरीब गुर्बा लोगों के लिए ये जीवन निर्वाह के साधन मुहैया नहीं कर पाये हैं। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। महंगाई के कारण, अन्न के अभाव के कारण लोगों को जो कष्ट होते हैं, उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिये। कितने ही आदमियों को बिना रोज़गार के अपना पेट जैसे तैसे भरना पड़ता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे यहां कहावत है "घर घर मटियाले चूल्हे हैं"। लोगों को किसी प्रकार पेट भरना तो पड़ता ही है। किसी प्रकार से भाग्य से आदमी अपना पेट भरता है, इस भाग्यवादिता का प्रभाव आप देखें

पौ फाटी पगरा हुआ, जागे जीवा जून।
सब काऊ को देत है, चोंच समाना चून॥

आप समझिये कि वह भी नहीं मिलता है।

जिस तरह से गरीब आदमियों को, मामूली आदमियों को, भाग्यहीन लोगों को, हरिजनों को, विशेषकर बाल्मीकी सांसी आदि को जबर्दस्ती पकड़ कर पुलिस अत्याचारी तरीकों से, ज़मींदारों के हाथ में रहने के कारण, तंग करती है, वह बयान नहीं किया जा सकता है। आप इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश की पुलिस मालदार व ज़मींदार आदि लोगों के हथकंडों में रहती है, उन्हीं के द्वारा चलती है और उनके कहने पर जबर्दस्तियां की जाती हैं, चालान किये जाते हैं। एक दो मिसालें मैं देना चाहता हूं।

एक बाल्मीकी लड़का जो कि बम्बई में नौकर था मेरे जिले में छुट्टी आया। उसको ही पुलिस ने 109 में चालान करके बन्द कर दिया। बेचारे ने बुरी तरह से रगड़े खाये और जैसे तैसे जाकर बाद में वह छूटा। यहां नई दिल्ली के एक हिस्से में दो मामूली आदमी, गरीब—गुर्बा आदमी अपने समधी को मिलने गये और उनको भी उठा कर पुलिस ने 109 में बन्द कर दिया और कुछ...

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप खत्म करें।

श्री बाल्मीकी: यह मुझे जाती अनुभव हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम गरीब लोगों पर जुल्म और अत्याचार होते हैं। इस धारा की भाषा बिल्कुल लचर है। आज भी समय है कि उस पर पुनः विचार हो। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान धारा 109 के साथ साथ 107, 108 और 110 की ओर भी आकर्षित करता हूं। गुंडा एक्ट की दृष्टि में आजकल तकड़ा होना भी जुर्म है। गरीब होना और उस पर तकड़ा होना जुर्म है। पुलिस मालदार आदमियों को, जमींदार आदमियों को कुछ नहीं कहती है, उनके हाथ में तो वह खेलती है। लेकिन गरीब लोगों पर जो अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इन जुल्मों से उनको बचाने के लिए माननीय मन्त्री जी का यह कर्त्तव्य है कि वह इस पर विचार करें। मैं डा० लोहिया के इस विधेयक के सम्बन्ध में अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करें और इसको मानने की चेष्टा करें।

Shri D. C. Sharma: Sir, I beg to support this Bill for various reasons. My first reason is that this Bill harks back to 1898. At that time, I think the attitude towards crimes was penal and punitive. Now the world has undergone a great deal of change and we are thinking of crime in terms of psychological rehabilitation and of occupational therapy. Therefore, the whole of this section needs drastic revision, in view of the changes that have taken place in this world during the last so many years.

My second point is that a great deal of reliance is placed here upon

intention. It says, "The Magistrate has reason to believe; that is, he can become a judge of a man's intention. How does anybody know what my intention is for Shri Balmiki? How can anybody guess what my intention is for Shri Kewal Krishna? I think, your intention is something hidden, something concealed, something unknown. It is known only to Almighty God and if the Magistrate is going to apprehend a person only on the strength of his intention, I think, he is arrogating to himself divine powers, powers of the Almight God, which I am not prepared to concede to him. Therefore, I believe that this is not the right approach.

It is said that a man may have an intention to commit an offence. How can anybody guess or judge anybody else's intention? Therefore, I believe that this is a very, very dubious approach to this problem.

Thirdly, it has been said that there should be ostensible means of subsistence. Who amongst us has any ostensible means of subsistence? What are the ostensible means of existence of a Member of Parliament? Does he till his land, run a factory or a shop, teach in a school or go to some other place of work? No.

Shri Rane (Buldana): He gets salary.

Shri D. C. Sharma: Therefore, the thing that the lack of ostensible means of subsistence can be made a crime, I think is something which is highly objectionable not only from the point of view of wording of the thing but also from the point of view of other things. There are some business executives in America and other countries of the world who do nothing, who only sit and yet who draw fabulous salaries. If you judge them by this ostensible means of subsistence, you can apprehend them under section 109.

Again, it is said. "If a man can give a satisfactory account of himself." I think, you cannot have a more wrongly worded phrase than this, a satisfactory account of himself. Can anybody give a satisfactory account of himself to anybody? I think, no husband can give a satisfactory account of himself to his wife; no son can give a satisfactory account of himself to his father; no father can give a satisfactory of himself to his son. We are all on trial. Fathers are on trial at the hands of their sons; husbands are on trial at the hands of their wives and the children are on trial at the hands of their fathers. To say that you have to give a satisfactory account of yourself is something which, I think, is given only to God and not to any magistrate.

Fourthly, if you look at the history of the world, you will find that in every country, in USA and other countries of the world, there are what are called hoboes, tramps or *apache* in France. They have no ostensible means of living; yet nobody apprehends them under section 109. They go about from one place to another; they do not earn their living; yet nobody apprehends them in that way. Then, there are a class of students, called beatniks. Why are not beatniks apprehended in USA and other countries of the world? They have no means of living so far as anybody can see.

I think, this section was introduced only by the British Government to be used as a hammer against those persons who differed from them politically, who differed from their policy and other things.

I know so many workers were apprehended under this section. Therefore, I say that our Home Minister, who is a very good judge of these things, should have this Bill circulated for eliciting public opinion so that we can either do away with this section or have something in its place which is in conformity with our provisions of the Constitution.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

Shri D. C. Sharma: One word more and I have done.

Now, a man who has no ostensible means of living, a man who has nothing of the kind, is asked to execute a bond. . . . .

An hon. Member: Surety also.

Shri D. C. Sharma: ....and to give surety also. It is like asking a blind man to produce a certificate of the fitness of eyes; it is like asking a cripple to produce a certificate which purports to be dealing with the fitness of his legs and it is like asking a weak man to give a certificate which purports to be a certificate of his physical fitness. I think, this Bill, on the face of it, is absurd in drafting, is *mala fide* in intentions and has been *mala fide* in its execution. It has done good to nobody except the police and, I think the sooner we end the police *raj* from this country, the better it will be for this country.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I only want to make a few observations on this Bill. I am not among those who will plead for the repeal of all Acts which are, more or less, of preventive nature. Though we have advanced a good deal, still we must say that the brutal side of the human nature has not become extinct. With that recognition, it is necessary for us to allow some sort of extra power in the hands of the Government to deal with that kind of element in the interest of law and peace. At the sime time, we must also see that we have proceeded in our legislation with a certain spirit of advance—progressive legislation as we call it—and the most notable example of that progressive spirit is presented in our Constitution by the chapter of Fundamental Rights. Not only that. Under our Constitution, anbody—if God favours—can occupy the seat which the hon. Member on the Treasury Benches occupies. The law of Criminal Procedure Code and all such other penal laws were made at a time when these ideals were not there and when all these progressive forces were not in existence.

15.34 hrs.

[SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

Now, the question is: Are we sincere in working them under that spirit or not? That is to be judged by the attitude we take in regard to those oppressive laws which have been made with different intentions and with different objectives altogether. It is clear from the speeches made here and also from my own experience that the good intention that is there in the beginning is certainly abused in many ways. If we do not want to repeal it, we should at least see whether it should be kept in the form in which they exist, whether the wording should be changed or not.

I shall give one example. Many persons have shown that when they want some kind of a person such as barber or sweeper to be put inside the jail, they manage to get hold of that fellow under this section and put him in jail. Now, it has been clearly held that the person dealt with under section 107 should not be treated as an accused. It cannot be used for such purpose. But such an abuse of power is being made under this section. We have to see whether the law, as it is, which is capable of being abused in this way, should stand or not. I, therefore, say that in view of the progressive spirit of legislation for which we stand, in view of the fact that we ourselves have created the Constitution in which a chapter on Fundamental Rights is there, in view of the fact that we have given franchise to every adult in this country who has the right to occupy the most responsible position in this country, should a law which was mainly meant for the cri-

minal tribes to bring them to the path of rectitude be allowed to remain now unchanged even under the altered conditions? We have to consider that.

My hon. friend, Mr. Trivedi, has suggested that the Bill should be circulated for public opinion or at least it should be referred to the Select Committee for its proper consideration. I support him in that. Although there is no formal motion made by anybody, yet it is open for the hon. Minister himself to take up this matter and not simply oppose the Bill on the strength of the majority which he may have got behind him.

Shri M. L. Jadhav (Malegaon): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill that is before us and my reasons for opposing the Bill are the following.

If you read this section, it says 'ostensible means of subsistence' or it refers to a person who cannot give a satsifactory account of himself. Somebody has said: How are we to gather intentions? Intention is a thing to be gathered from the facts and the circumstances that are prevalent. It is not that any policeman can go and arrest anybody. He must have some material, some evidence, to show that the person concerned is not in a position to give his particulars. Many a time, it happens that the person does not give his proper name. He tries to give one name at one place and another name at another place. He does not try to give his proper address and his means of livelihood. When he does not disclose these things, then along the police proceeds in the matter. This section is not a punitive section but it is a section which is preventive. Unless and until some preventive powers are given to the police, it is not possible to check unhealthy and bad elements in the society. Unless and until that is done, it would be impossible for the people to live in society and it would be difficult to have checks and counter-checks against persons who try to do any mischief in one way or the other. I find there are people who do live in the society and who do not want to do anything and they want to have their means of livelihood by some means which are not permitted by the society. They stay there as a burden to the society and it is very necessary that such elements who do not want to follow any profession at all and who want to maintain themselves by some means which are unhealthy or bad in law should not be encouraged.

I think, the removal of this section may create havoc in the society. I know that sometimes the section might have been misused by the police. But that does not mean that the law has been misused and that the section should be removed or the law should be annulled. I can understand that the better administration of the law is desirable and from that point of view, I feel, that whatever loopholes, whatever bad things, are there which have been practised by the police under the protection of this section, need to be removed. In that case, some improvement is needed. It does not mean that the whole section should be taken out of the law or the law should be annulled.

In these circumstances, I feel that the Bill that is before the House is not necessary and, therefore, I oppose this Bill.

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, यह धारा 109 वास्तव में हमारी कानून व्यवस्था पर और दण्ड विधान पर एक लांछन है और मैं समझता हूं कि किसी और

[श्री श० ना० चतुर्वेदी]

धारा का इतना दुरुपयोग नहीं होता जितना कि इस धारा का होता है । काफी लोगों ने इस के बारे में कहा है ।

सब से बड़ी बात तो यह है कि जहां पर इस धारा के अधीन आदमी पकड़े जाते हैं वहां उन के पास अपनी सफाई देने की गुंजाइश नहीं होती । वे रास्ते चलते पकड़ लिए जाते हैं, कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं वहां पकड़ लिए जाते हैं । वह इस बात का सबूत या शहादत नहीं दे सकते कि वे किस लिए वहां गए थे । और न यह देखा जाता है कि जो वह कहते हैं वह सही है या नहीं । यह पुलिस अफसर पर निर्भर करता है कि वह उस की बात माने या न माने । इस सम्बन्ध में मैं अपने अनुभव की एक दो बातें आप के सामने रखना चाहता हूं ।

एक बार यहां पर जो आजकल एक बड़े अफसर हैं उन के साथ साथ मैं भी गश्त पर गया हुआ था । रात में हम लोग जा रहे थे, कोई एक या दो बजे का समय होगा । तो देखा कि दो सिपाही एक आदमी को लिए चले आ रहे हैं । हमने पूछा कि क्या हुआ तो सिपाहियों ने कहा कि हुजूर कि इस आदमी को छिपा देख कर हम ने हल्ला मचाया जिस पर बहुत से आदमी निकल आए और हमने इसको गिरफ्तार कर लिया । मेरे साथी ने मुझ से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है क्योंकि मैं इन चीजों को शंका की दृष्टि से देखता था । मैं ने कहा कि पहले तो आप और हम हल्ला मचा कर देखें कि कोई आदमी निकलता है या नहीं । खैर वह बात तो वहीं रही । हमने उस आदमी को अलग ले जाकर पूछा कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया । उसने कहा कि मैं रोजी की तलाश में आया था, मैंने देखा कि एक फुटबाल का मैच हो रहा है तो मैं उसे देखने रुक गया । नीचे से अच्छा नहीं दिखायी देता था इसलिए पेड़ पर चढ़ कर उसे देख रहा था । मुझे इन सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जा कर चौकी पर रखा और इस वक्त मुझे थाने में लिए जा रहे हैं । मैंने उससे कहा कि उस चौकी के कमरे के बारे में बताओ जहां तुम को रखा गया था तो उसने उसका सही चित्र खींच कर रख दिया । उसने बताया कि किस जगह उसको खाना दिया गया था, किस जगह सुराही रखी थी, किस जगह कपड़े टंगे थे । उसकी वहां हम ने जांच कर ली तो उसको छोड़ दिया गया । अगर ऐसा न होता तो उसको न छोड़ा जाता ।

होता यह है कि जब किसी इलाके में जुर्म ज्यादा होते हैं और ऊपर से पूछा जाता है कि तुम ने प्रिवेंटिव ऐक्शन क्यों नहीं लिया तो इस तरह से कुछ आदमियों को पकड़ कर उनका चालान इस दफा में करा दिया जाता है और यह समझ लिया जाता है कि हम ने अपना काम कर दिया । और इस में ज्यादातर गरीब आदमी ही मारे जाते हैं ।

इस देश में जहां इतनी बेकारी है, ऐसे लोग जो रोजी की तलाश में होते हैं वे इस कानून में आ जाते हैं क्योंकि वे कोई आस्टेंसिबिल मीन्स आफ सबसिसटेंस कैसे बतला सकते हैं ।

इस सिलसिले में दूसरा किस्सा और सुन लीजिए । एक सज्जन कोतवाल थे । उनके एक रिश्तेदार आए और उन्होंने कहा कि हमारे दो लड़के बेकार हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता उनकी

रोटी का कुछ प्रबन्ध कर दीजिए । उन्होंने कहा बहुत अच्छा । उन्होंने उन लड़कों को ले कर दफा 109 में बन्द कर दिया और कहा कि एक साल की रोटी का इन्तिजाम तो कर दिया है । आगे तुम देखना ।

श्री राम सेवक यादव : इन लोगों को यह न बताइए, नहीं तो ये भी इससे फायदा उठाने लगेंगे ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : तो मैं इस धारा को हटाने के पक्ष में हूं । आज हमारा संविधान है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं । उस के साथ साथ ही अगर इस प्रकार की धारा भी रहे तो इस से बुरी और क्या बात हो सकती है । इसलिए मैं सिलेक्ट कमेटी में इस के भेजे जाने का समर्थन करता हूं ।

Mr. Chairman: The motion for reference of the Bill to a Select Committee was not moved; only the motion for circulation of the Bill was moved.

Shri S. N. Chaturvedi: Then, I support the motion for circulation.

Shri K. K. Verma (Sultanpur): Many hon. Members have spoken on the Bill before us, both for and against it. But I think that those who have spoken for the Bill have stressed more on the maladministration of the police or some wrong judgments that may have been there. But so far as the enactment is concerned, I do not think that there is any great flaw in it, and I feel that a wholesale annulment of this section would prejudice the ordered progress of our society. We live in an ordered society and I think that there can be no objection to the principle that offences should be prevented. It is no use if we merely arrest a person when he has already committed an offence. The instance of the murder of the ex-Chief Minister of Punjab, Mr. Kairon has been cited as also that of the late Solicitor-General. There are several instances in our country where preparations are made for committing an offence. I do not know how there can be any objection to the principle that where preparations are being made for committing an offence they should be prevented. Do you mean to say that you can arrest a person only when an offence has been committed, when murders have been committed or when dacoity has been committed? Do you mean to say that the police should come on the scene only after the offence has been committed and before that you cannot touch that person? I do not think that in an ordered society this can be conceived of that preparations for committing an offence should not be prevented. I do not think that any progressive country can think of the idea that the police should keep silent and should have no powers to prevent the commission and the preparation for the commission of an offence.

Sub-section (a) of section 109 reads thus:

> "that any person is taking precautions to conceal his presence within the local limits of such Magistrate's jurisdiction and that there is reason to believe that such person is taking such precautions with a view to committing any offence.".

I do not think that there can be any objection to this sub-section. The only objection that was raised was raised by Shri D. C. Sharma who said that this meant giving very wide powers to the magistrate, and he asked how a magistrate could be relied upon, because the wording here is:

> "that there is reason to believe that such person is taking such precautions with a view to committing any offence.".

Then Shri Sharma argued that this has been left to the whims of the magistrate. I do not think so. Nowhere has the court been given such

[Shri K. K. Verma]

powers and nowhere can a magistrate exercise that power arbitrarily. His discretion has to be judicial discretion. It has to be based on certain circumstances and certain evidence. So the wording that 'there is reason to believe that such person is taking precautions with a view to committing an offence—this conclusion cannot be arrived at on the basis of the arbitrary thinking of a magistrate; it has to be based on certain evidence and certain circumstances.

Now we come to sub-clause (b) 'that there is within such limits a person who has no ostensible means of subsistence, or who cannot give a satisfactory account of himself'.

Dr. M. S. Aney: Is he reading 106 or 107?

Shri K. K. Verma: I am reading from sec. 109 which is sought to be deleted.

In the statement of objects and reasons, Dr. Lohia has said:

> "Section 109 of the Code of Criminal Procedure, 1898, is against the dignity of the citizens of a free country. It makes unemployment a punishable offence, whereas the Government is not prepared to undertake responsibility for the unemployed. Moreover, it makes punishable not an offence but the likelihood of an offence which is against the fundamental principles of jurisprudence".

I have already submitted that the likelihood of an offence, that is, preparation for an offence, has to be checked if there is to be ordered government in the country which vouchsafes the safety of the citizens.

The second point made out in the statement of objects and reasons is that it makes unemployment a punishable offence. I do not know whether the framer of this Bill knows what is the settled law of the country. If he had known it, I think he would not have used the words 'it makes unemployment a punishable offence..'. The settled law of the country is that by itself unemployment is not an offence.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Should be an offence. Then Government will solve the problem.

Shri K. K. Verma: Perhaps the hon. Member is then subscribing to what Chaturvedi said.

Shri S. M. Banerjee: You draft it. You are a lawyer.

Shri K. K. Verma: I have already said that maladministration is another thing. The enactment of the present section as it is is different from that. If you have a grudge or grievance against maladministration, there are other remedies which can be resorted to.

I may quote from a judgment of Justice Page where he has said:

> "Merely to be penniless or out of work is not an offence. Many an honest man may find himself in either predicament. If a person is unable to prove the source of his livelihood, he cannot be brought within sec. 109 unless there is reasonable ground for suspicion that he is sustaining himself by dishonest means".

That is the criterion for punishing that person. It is not that he should prove the source of his livelihood, but the burden is on the prosecution to prove that such a person is sustaining himself by dishonest means. The court is not going to punish him or call upon him to execute a bond or surety unless the prosecution satisfies the court that the accused is sustaining himself by dishonest means. Therefore, I think the settled law of the country does not admit mere assertion of the charge levelled against a person. It has to be proved to the satisfaction of the court. If you have a grievance

against maladministration by the police, the Home Minister is here and the States are there. They can be approached to take suitable remedial action.

Another point—'who cannot give a satisfactory account of himself'. In that respect also, the prosecution has to satisfy the court that that person is living dishonestly. I think in a progressive society dishonest persons have no place.

I oppose the Bill.

Shri S. M. Banerjee: I rise to support the Bill framed by Dr. Lohia but actually moved by Shri Yadav.

Previously also, I remember we did our best to highlight this problem of arresting people without any ground under s. 109. I had the privilege to go to various jails under the Congress regime, and I have seen that 50 per cent of the jail population is under s. 109. If a survey is made by the Home Minister by appointing some committee to find out as to who are those who are cooking in the jails, working as barbers, *kumhars*, sweepers and others, he will surely come to the conclusion that they are only those who are arrested under s. 109.

I know of an instance when I was in the Kanpur jail in 1947. When we agitated for more *surahis*, water carriers, we were told by the Jail Superintendent that they were in search of *kumhars* who could manufacture these things and 'we shall get them in a day or two'. After two days, we saw that 13 or 14 people were arrested from Raniganj which is an area populated by *kumhars*. It struck me that they might have been arrested under s. 109. It was confirmed when I asked them under what section they were arrested. They said '109'. That is how people are brought inside the jail.

I would therefore say that this is not a preventive measure at all. This is a sharp instrument used by the police to arrest anyone who they find roaming about, even in search of a job. Today, as my hon. friend, Shri Verma said, to become unemployed or unemployment, is not a crime. Had it been made a crime in this country, I think the Government in power would have tried to solve this problem.

Now, what is the guarantee here? It has been brought to my notice the other day that the Home Minister of a State, Punjab, gave protection in writing on a file to the biggest smuggler of Punjab. It was objected to by the IG, Police, who said that a warrant had been issued against him and he was going to be arrested. But the Minister maintained, 'No, he should be given protection'. If the papers are seized, I am sure the Home Minister will come to the conclusion about what is going to be the fate of this country if the Home Minister of a State gives protection to the biggest smuggler. Ultimately, the file was taken by the Chief Minister, and the man was arrested.

Shri Hathi: Section 109?

Shri S. M. Banerjee: Not 109. There are other serious charges. Supposing s. 109 were used to prevent crimes, they would have arrested those people who are holding the country to ransom. But who are arrested?—unemployed youth, landless labour who come from the villages in search of jobs in some of the factories or industrial places like Kanpur, Calcutta, Ahmedabad and other places. They are put in jail.

16 hrs.

Once a person is arrested under section 109 and is unable to furnish bail, he is arrested every time, and then he is called a *dubaria* or a *tibaria*. A *dubaria* is given a uniform with two stripes.

I know that a person who is facing unemployment knows no law, and by sending these people to jail, this Government is making them hardened criminals. I should remind the House

[Shri S. M. Banerjee]

and the hon. Minister of one line from Alexander Dumas. When society ruins him, snatches everything from him, sends him to jail and makes him a hardened criminal, Dante, the hero of the story, says: "Overturn the world, change character, yield even to mad ideas, but live." This becomes the psychology of the minds of those who are put in jail, not for reforming them.

What is happening in the jail? Sweet words are written throughout the jails now, like: 'लोगों से मीठा बोलिये'. And exactly there, the men are beaten. I do not know what is going to happen.

So, these sections 109 and 110 are used indiscriminately by the police, and I congratulate Dr. Lohia, and the mover of the Bill, Shri Ram Sewak Yadav, for highlighting this problem, and I am sure this should be done away with.

I have mentioned the case of the Home Minister of Punjab giving protection to a criminal. I want this to be enquired into by the Union Home Minister without any fear. Otherwise, I do not know what is going to be the fate of this country if the Home Minister of a State acts like that. I request him to kindly make a note of it and not to reply to it immediately—I am sure he is not going to defend the Home Minister of Punjab —but to make necessary enquiries and inform the House at the time the Demands of the Home Ministry are discussed.

Shri Hathi: This Bill, moved by Shri Yadav, seeks to delete section 109 of the Code of Criminal Procedure. The Statement of Objects and Reasons of the Bill says:

> "Section 109 of the Code of Criminal Procedure, 1898 is against the dignity of the citizens of a free country. It makes unemployment a punishable offence, whereas the Government is not prepared to undertake responsibility for the unemployed. Moreover, it makes punishable not an offence but the likelihood of an offence which is against the fundamental principles of jurisprudence."

श्री ओंकार लाल बेरवा : सभापति महोदय, कोरम नहीं है। अगर हाउस के सामने कोई गैर-सरकारी बिल है, तो वह भी तो मान्यता रखता है, इस लिए कोरम रखना जरूरी है। मंत्री महोदय रेप्लाई दे रहे हैं।

Mr. Chairman: The bell is being rung.....Now there is quorum.

Shri Hathi: The main arguments of the hon. Mover are, firstly, that this is against the dignity of the citizens of a free country; secondly; that it gives power to take security and even arrest persons who have no employment; and thirdly that the powers are misused, that the police misuse the powers in a high-handed manner.

Of the Members who supported this Bill, Shri Trividi and Shri Chatterjee made observations not quite to support the deletion of the section. Because they thought that there must be some power to regulate the society. Dr. Aney also was not quite opposed to giving some power to the Government to regulate the conduct of the society. Whatever may be the institution or organisation or form of government in any walk of life, some regulatory powers are necessary to see that the society goes on smoothly without any danger or breach of peace. Some Members said that sections right from 107 to 111 or 117 should be deleted. But the main argument that was put forth was that this provision of law is being used by the police to harass the poor people, without any means and people who cannot explain

their whereabouts. It would be proper for me to refer to section 109 which is divided into two parts. The first part says that whenever a presidency magistrate or a district or subdivisional magistrate or a magistrate of the first-class receives information that any person is taking precaution to conceal his presence within the local limits of such a magistrate's jurisdiction and that there is reason to believe that such a person is taking such a precaution with a view to committing an offence, that there is within such limits a person has no ostensible means of subsistence or who cannot give a satisfactory account of himself, such a magistrate may in the manner hereinafter provided, require such a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with sureties for his good behaviour for such period not exceeding one year. Therefore, if we look to the section it is not that the police can arrest anybody whom they see Shri Chaturvedi narrated a story when the police arrested a man who was hiding in a tree, ultimately it came about that the man was released because the powers are not with the police. This is not an executive power. This is a judicial matter. It has been held in a number of cases that this section is not to be used only for roping in somebody. That is the settled law of the country. Our judiciary is independent. This is a judicial matter. It is not an executive matter. It has to be proved that a man was hiding with a view to commit an offence or that the man was living with means which he could not explain. It does not mean unemployment; that means some thing different. So far as the law is concerned, the magistrate has to take particular care that the police do not make use of the other branch of this section to retain or rope in any person with whom they have some displeasure and against whom they could not prove any offence. The law is clear. It is the judiciary which is in charge of seeing that the laws of the country are implemented in a manner consistent with the democratic system of government and the rights of the citizens. It is not merely the executive or the police that have got unfettered power to rope in anybody and put him in jail. There may be a man arrested by the police. But it is not that merely because he is arrested, he is asked to give a bond. The procedure is that he is asked to show cause why a bond for good behaviour should not be given. Even before, the magistrate should have reason to believe that this man is going to commit an offence. Unless the magistrate is satisfied, no order would be made and so it is not right to say that the police can arrest anybody.

Coming to second part, the emotional part, it is a part which would move everybody everybody would be moved naturally when the hon. Mover touched the finer sentiments in every one of us. If a man is unemployed, he is asked to go to jail—and there are thousands of people who are unemployed. If 109 remains as it is, all these people will be sent to jail. That is what he says.

Shri Heda (Nizamabad): Judiciary at the lower levels is not independent in every State.

Shri Hathi: He says that unemployed people would be roped in. We have to make a very clear distinction. It is not as if a man simply because he has no livelihood, will be sent to jail. The meaning here is this. A man is living in a very fine way, in a way in which he could not normally live unless he was earning very much; still he is living in a pompous way.

Shri Ram Sewak Yadav: Then, the DSPs, Inspectors and S.Is. should go to jail.

Shri Hathi: Supposing, he is living only by gambling or by dealing in stolen property or by smuggling would be reveal his means of livelihood if he were to be asked about it? He would not come forward and say that he lives on smuggling or gambling. If he could not give out his ostensible

[Shri Hathi]

means of livelihood by itself that is no offence but when he is living in a way in which he could live only if he is earning quite well, by dishonest means it is only in such cases that this has to be used. This is a very settled and definite law. Shri Chatterjee who is a lawyer of repute is not here now. But I am glad that he did not say that the courts have abused this. I would like him or anybody to show a single case in all these years where a man has been detained or arrested under section 109 only on the ground that he was unemployed.

Shri Sarjoo Pandey: We can cite a thousand cases.

Shri Hathi: One might have been suspected or it might have been apprehended that one was going to commit an offence, but it is a different matter. There is not a single case where purely and simply, on one single ground that he had no means of livelihood, a man has been detained or arrested or asked to give a bond of good behaviour. I have a number of cases where, in every judgment, it has been held that merely to be penniless or out of work is not an offence. Many an honest man may find himself in either predicament. If a person is unable to prove the source of his livelihood, he cannot be brought within section 109 unless there is reasonable ground for suspicion that he is sustaining himself by dishonest means. The point to note is that to have no visible means of livelihood is not offence. The question is whether he earns his livelihood by illegal means. It is only to the latter that section 109 can be applied. So, in the absence of evidence of dishonest means of existence, a person cannot be bound over. A person who is doing no work cannot be boud under section 109. There are a dozen cases where courts have always held that unemployment by itself is not a ground for taking the surety under section 109.

Therefore, I can give this categorical assurance that section 109 is not to be used, and if there are cases here and there where that is being misused, it is a question where we have to go into it and see whether the powers had been misused by the police. But that is a different matter and that is a question of administration. If these powers are misused, every man has a right to go to a court of law. Some Members said that the magistrates are not in several cases independent, but then the district judges and the high courts are independent. (*Interruption*). There is no question about it. Therefore, the mere fact that section 109 is used to take security for good behaviour from people who have no means of livelihood is not a correct proposition of law. The correct proposition of law is that if a man has a livelihood but cannot show the ostensible means of that livelihood as to where from he gets money—

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): We agree with you, but what we say is that the police does not interpret it as you are doing.

Shri Hathi: That is the interpretation given by all the courts of law. (*Interruption*). Therefore, the question is, if the police misuse the power, it is a matter not for repeal of the Act but for improving the administration. (*Interruption*). Supposing, for example, in a genuine case where a man is out to commit a murder of somebody —taking a hundred per cent sure case —or a man is found roaming about a certain place with a view to commit theft, and if in that one case the police has got this information and if they have not got the power to arrest and take the man before the magistrate, how will you stop this crime? Therefore, this is a measure for preventing a crime. I agree with the point that if the power is misused, it has to be looked into, but the remedy is not by repealing the provision. (*Interruption*).

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

16.25 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Hathi: If you repeal it, there will be no power with anybody to prevent an offence, and I am sure that everybody who has spoken has been in favour of giving some powers to prevent offences. Where powers are to be given to stop offences or to prevent offences, nobody is opposed to it. All that has been said is that this is being misused. The powers should not be misused, but that is a different matter.

Now, I shall read section 110. It says:

> "A person who is by habit a robber, house-breaker, thief, or forgerer, or is by habit a receiver of stolen property knowing the same to have been stolen...."

This is the provision of section 110. If you do not give the authorities the power to deal with these people, what will happen? Of course, we want freedom and we want the people to express themselves and to behave as they like, and we are for the dignity of the person. I personally do not at all say that the movement of a man must be restricted. Our Constitution provides liberty and we also respect the dignity of everyone of us. But we cannot say that the society is free of people who are given to commit crimes. If we have not even the powers to deal with these people, then there will simply be inaction of law and order and there will be nothing to regulate the society and nothing by which we can prevent, the offences.

As I said, if a man happens to be unemployed, that by itself is no offence. There are certain other things to be collected. Then, it is not that the police can simply bring a person to the magistrate for orders. He has to satisfy himself. Shri D. C. Sharma asked how is one to know the intentions of the man. It is not a question of knowing the intentions merely with a divine power; the magistrate has to record the evidence which the man produces and after the evidence is recorded and he is satisfied, then only he issues the order, but before that, there is a procedure prescribed, and that is, he is bound to issue a notice to show cause why the person should not be bound. If the cause is shown, then there is no question of his being bound down by any bond of security. If the man cannot give sufficient reason for his movement, for his doing certain acts, then only, if the magistrate is satisfied, this section is to be used.

Therefore while I would agree that the powers should not be misused, I cannot agree to the deletion of section 109 by itself. Then there are so many other sections which will also have to be recast. If you say that section 109 is misused, you can as well say that sections 110, and 112 and so on are all being misused. Therefore, something has to be done. But I may say that we have already referred the whole of the Criminal Procedure Code to the Law Commission; they are examining it. Looking to the present state of society, we have even to include certain offences called social offences. We have referred the whole thing to the Law Commission and whatever is consistent with the present state of society, will be done. Now, as we are moving further and are developing, it is not simply a question of crime; there is a background to the crime and more of social crimes are coming. For that also we will have to see what could be done. As I said earlier, we are also thinking of dealing with social offences. These offences are more dangerous to society in a developing economy.

We are referring it to the Law Commission to suggest what amendments should be made looking to the needs of the society at present.

So far as this Bill is concerned, I am not agreeable to deleting section

[Shri Hathi]

109 alone. I would, therefore, request Mr. Yadav, who is otherwise a reasonable person, to agree to withdraw this Bill.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल और खास तौर से उसके मंत्री 15 अगस्त सन् 1947 के बाद ज्यादा बुद्धिम न हो गए हैं या पहले ज्यादा बद्धिमान थे, क्योंकि जब हम अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे तो हर आदमी के मुंह से यह आवाज निकती थी कि धारा 109 जाब्ता फौजदारी गरीबों को सताने के लिए है, इसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन दुःख की बात है कि कि वही लोग जो इस धारा के खिलाफ बोलते थे आज 15 सालों में नौकरशाही के हाथों में पड़ कर ऐसे हो गए हैं कि इस किस्म की धारा को रखने की बात करते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि रानी सिगरौली की हत्या हुई। उसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है और सदन के एक सदस्य का हाथ है लेकिन आपके अधिकारी और आप की पुलिस आज तक उनको छू नहीं सकी। आज तक उसका पता नहीं लगाया जा सका। एक हत्या हो गयी, एक सब्सटेंटिव आफेंस हो गया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कैरों की हत्या में भी शायद यही होने वाला है।

क्या जो गरीब आदमी दफा 109 में पकड़े जाते हैं वे हत्या करते हैं या कत्ल करते हैं। आपने स्मगलिंग का हवाला दिया। मैं आपको बतलाना चाहता हू कि आज जो अफीम का या सोने का स्मगलिंग हो रहा है उसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, जो इस समाज में बड़े लोग और सफेदपोश लोग हैं।

मंत्री महोदय ने हमको हाईकोर्ट के कुछ फैसले पढ़ कर सुनाए। यदि आप उन फैसलों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि वे हमारे हक में जाते हैं। इस दफा में जो गरीब लोग पकड़े जाते हैं उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होता। ऐसे लोगों का इस दफा में चालान किया जाता है। इन लोगों के कपड़े फटे होते हैं इनके पैरों में जूते नहीं होते। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह के लोगों को पुलिस इस धारा में पकड़ लेती है। एक सज्जन हैं जो आजादी की लड़ाई में लड़ चुके हैं। उनका लड़का दिल्ली में नौकरी की तलाश में आया था। उसे पुलिस ने पकड़ कर इस धारा के अधीन बन्द कर दिया था। तो जिन गरीब लोगों के पास खाना नहीं कपड़ा नहीं, जिनके पास अपने बचाव के लिए पैसा नहीं उनको इस धारा में गिरफ्तार किया जाता है। और कह दिया जाता है कि इस के पास कोई जीविका का जाहिरा साधन नहीं है। और मजिस्ट्रेट उनको सजा दे देते हैं। कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के सामने इन लोगों को पेश किया जाता है। लेकिन ये लोग इतने गरीब होते हैं कि अपना बचाव भी नहीं कर सकते।

हमको जो फैसले सुनाए गए हैं वे हाईकोर्ट के हैं। हाईकोर्ट कितने लोग हैं। और जब जब ये मामले हाईकोर्ट गए उनको रद्द कर दिया गया है। जो दलील मंत्री महोदय ने दी है वह तो हमारे हक़ में जाती है। इस धारा के द्वारा तो गरीब लोगों को ही तंग किया जाता है।

मंत्री जी ने कहा कि पुलिस तो केवल चालान करती है, इतने से ही सजा नहीं हो जाती। बाद में केस मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। यह ठीक है कि फैसला मजिस्ट्रेट करता है लेकिन उस आदमी के पास तो साधन ही नहीं है, वह क्या सफाई और सबूत पेश कर सकेगा। पुलिस के हाथ में इतना बड़ा जबरदस्त हथियार है कि जिसके पास जीविका का साधन न हो उसको पकड़ कर भेज देते हैं। और जहां तक मजिस्ट्रेटों का सवाल है हिन्दुस्तान में ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जूडीशियल मजिस्ट्रेट सेशन या हाईकोर्ट के अन्डर

नहीं होते। वे कलक्टर के माहतहत होते हैं और धारा 109 के मुकदमे उनके ही सामने जाते हैं। ये एक तरह से पुलिस मजिस्ट्रेट होते हैं और कानून का दुरुपयोग होता रहता है।

प्रशासन की बात कही जाती है। मैं कहता हूं कि प्रशासन के लिए तो आपके खजाने में बहुत से हथियार हैं। जो बड़ी घटनाएं घट जाती हैं उनके मुजरिमों को तो पकड़ा नहीं जाता। कारगुजारी दिखाने के लिए ऐसे गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह कानून हमारे संविधान पर कलंक है और इस देश में जहां कि लोग इतने गरीब हैं और जिनके पास रोटी रोजी नहीं है, उनको इस धारा के अधीन गिरफ्तार करना न्यायसंगत नहीं है।

वर्मा जी ने कहा कि नहीं इस का गलत इस्तेमाल नहीं होता है। वे कहते हैं कि यह संविधान के प्रतिकूल नहीं है बल्कि इससे तो सोसाइटी की रक्षा होती है। मैं कहना चाहूंगा कि इससे सोसाइटी की रक्षा नहीं होती बल्कि अच्छे लोगों को अपराधी बनाया जाता है और इस देश की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है।

पराशर साहब शायद नई वकालत करना चाहते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि यह धारा कायम रहे जिससे इस तरह के मुकदमे आते रहें और उनको गंजाइश हो जाए। वह हम को इस धारा को पढ़ाने लगें। लेकिन अगर वह भी अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो उनको पता लगेगा कि आज इस धारा के द्वारा इस गरीब देश में गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वैसे अनेकों धाराएं बहुत खराब हैं, जैसे 107, 108, 110 आदि। पर धारा 109 का गरीबों पर बड़ा दुरुपयोग होता है। यह पुलिस के हाथ में बड़ा जबरदस्त अधिकार है। जो वास्तविक गुंडे हैं उनको तो एक तिकोण है। वे पकड़े नहीं जाते हैं। उनको जगह 109 में कुछ लोगों को पकड़ कर दिखा दिया जाता है। मेरा खयाल है कि प्रताप सिंह कैरों के मामले में भी असली गुंडों को नहीं पकड़ा जाएगा और इसी तरह के लोगों को पकड़ कर दिखा दिया जाएगा।

संविधान की धारा 19 में जो नागरिकों को अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए और उनको अपने उन भाषणों की भी कुछ लाज रखनी चाहिए जो वे आजादी के पहले दिया करते थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर फिर विचार किया जाए और इसको ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाए। या उसको जनमत संग्रह के लिए भेज दिया जाए। मेरे एक माननीय मित्र ने ऐसा प्रस्ताव दिया है। मैं उसको स्वीकार कर सकता हूं। अगर इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाएगा तो सरकार को लोगों की इस के बारे में राय मालूम हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जनमत जानने के प्रस्ताव को सरकार क्यों नहीं मानती।

अन्त में मैं पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया है। सदन का विशाल बहुमत इस धारा को हटाने के पक्ष में है।

Mr. Deputy-Speaker: I shall first put the amendment to the vote of the House. The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st August, 1965".

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Now I shall put the main motion. The question is:

"That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898 be taken into consideration."

The motion was negatived.